

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

20 February 2026



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: The Reserve Bank of India (RBI) granted final approval to Bain Capital affiliates to acquire joint control and up to what percentage stake in Manappuram Finance?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी?

- A) 26%
- B) 33%
- C) 41.66%
- D) 49%
- E) 51%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has granted final approval to affiliates of Bain Capital to acquire joint control and up to 41.66% stake in Kerala-based Manappuram Finance.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को केरल स्थित मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम 41.66% हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी है।
- This approval clears the way for the completion of Bain Capital's ₹4,385 crore investment in the gold loan-focused NBFC.
- इस मंजूरी से गोल्ड लोन पर केंद्रित NBFC में बेन कैपिटल के ₹4,385 करोड़ के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- Bain Capital was founded in 1984 and is headquartered in Boston, Massachusetts, USA.
- बेन कैपिटल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में स्थित है।
- Manappuram Finance was originally founded in 1949 and is headquartered at Valapad in the Thrissur district of Kerala.
- मणप्पुरम फाइनेंस की मूल स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर ज़िले के वलापाड में स्थित है।
- It is a Non-Deposit Accepting Loan Company and is classified as a Systemically Important Non-Banking Financial Company (NBFC-ND-SI).
- यह एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली ऋण कंपनी है और इसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय





कंपनी (NBFC-ND-SI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- Deepak Reddy assumed charge as the Chief Executive Officer (CEO) of Manappuram Finance on August 1, 2025.
- दीपक रेड्डी ने 1 अगस्त 2025 को मणप्पुरम फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला।



EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to RBI

- As per the master directions issued by Reserve Bank of India, the maximum permissible cap for a Default Loss Guarantee (DLG) is limited to 5% of the loan portfolio.
- RBI के मास्टर निर्देशों के अनुसार, डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) की अधिकतम सीमा ऋण पोर्टफोलियो के 10% तक सीमित है।
- Reserve Bank of India (RBI) issued draft guidelines in February 2026 to streamline the Lead Bank Scheme (LBS) with a focus on improving credit flow in rural and semi-urban areas.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में लीड बैंक स्कीम (LBS) को सुव्यवस्थित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।
- Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to extend aggregate exposure up to 20% of their eligible capital base for acquisition (M&A) financing, increased from the earlier proposed 10%.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अधिग्रहण फाइनेंसिंग के लिए बैंकों को अपनी पात्र पूंजी आधार का 20% तक कुल एक्सपोजर देने की अनुमति दी है, जो पहले प्रस्तावित 10% था।
- Reserve Bank of India (RBI) has been publishing the RBI–Digital Payments Index (RBI-DPI) since 1 January 2021, with March 2018 as the base year (Index = 100).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 जनवरी 2021 से RBI–डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) प्रकाशित कर रहा है, जिसका आधार वर्ष मार्च 2018 (इंडेक्स = 100) है।
- The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive draft directions on advertising, marketing, and sales of financial products and services by banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित व्यापक ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं।
- Reserve Bank of India (RBI) has proposed to double the aggregate ceiling of unsecured advances for Urban Cooperative Banks (UCBs) to 20% of total assets, from the earlier limit of 10%.





Ques: NPCI has partnered with which company to advance its sovereign AI model for digital payments?

NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए सॉवरेन AI मॉडल को आगे बढ़ाने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Nvidia / एनवीडिया
- B) Google / गूगल
- C) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- D) IBM / आईबीएम
- E) Amazon / अमेज़न

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has partnered with Nvidia to scale and advance a sovereign AI model for India's digital payments ecosystem.
- NPCI ने भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए सॉवरेन AI मॉडल को विकसित और विस्तारित करने हेतु Nvidia के साथ साझेदारी की है।
- The initiative focuses on building AI capabilities aligned with India's regulatory framework and data sovereignty requirements.
- यह पहल भारत की नियामकीय व्यवस्था और डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के अनुरूप AI क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।
- NPCI will leverage Nvidia's advanced AI and accelerated computing platforms, including Nvidia Nemotron models.
- NPCI, Nvidia के उन्नत AI और accelerated computing प्लेटफॉर्म, जैसे Nvidia Nemotron मॉडल्स, का उपयोग करेगा।
- The collaboration aims to enhance trust, resilience, security, and efficiency in large-scale real-time payment systems.
- इस सहयोग का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रियल-टाइम भुगतान प्रणालियों में भरोसा, लचीलापन, सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करना है।





Ques: What key change has the Reserve Bank of India (RBI) introduced regarding Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) को लेकर कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Banned the use of DLGs permanently / DLG के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाया
- B) Allowed DLGs only for banks, not NBFCs / DLG केवल बैंकों के लिए अनुमति दी, NBFCs के लिए नहीं
- C) Restored the use of DLGs for NBFCs in loan loss provisioning / NBFCs को ऋण हानि प्रावधान में DLG शामिल करने की अनुमति दी
- D) Increased the cap on DLGs to 10% of loan portfolio / DLG की सीमा 10% तक बढ़ाई
- E) Allowed DLGs only for government-backed fintechs / DLG केवल सरकारी समर्थित फिनटेक्स के लिए अनुमति दी

Answer: Option C

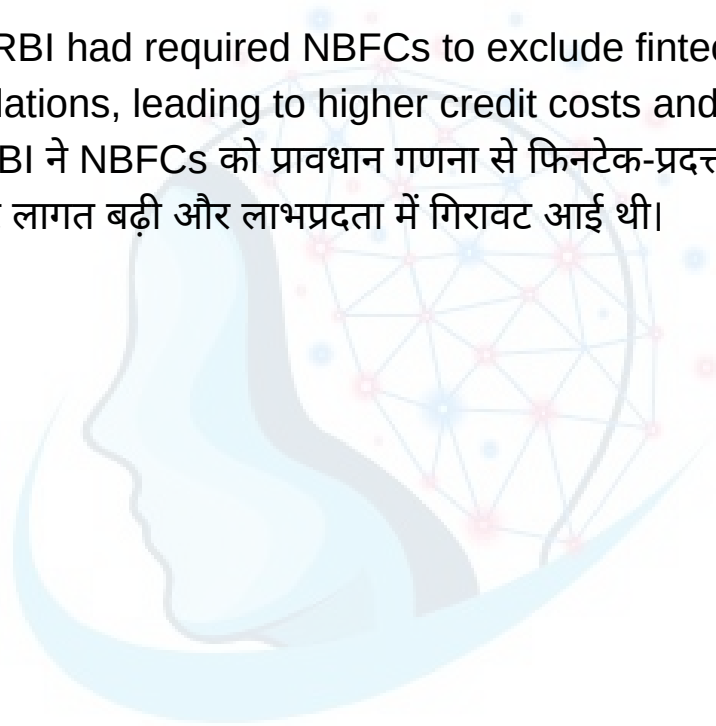
Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has restored the use of Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders, reversing its curbs imposed in May 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेते हुए गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) के उपयोग को बहाल कर दिया है।
- Under the revised framework, NBFCs can again factor in DLGs while calculating loan loss provisions, and the changes take effect immediately.
- संशोधित ढांचे के तहत NBFCs अब ऋण हानि प्रावधान की गणना में DLG को शामिल कर सकती हैं और यह व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।
- The guarantee must be an integral part of the loan arrangement and cannot be treated as a separate standalone protection.
- यह गारंटी ऋण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और इसे अलग सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा।
- Loss estimates must be updated every time the DLG is invoked, as the level of protection reduces with each utilisation.
- प्रत्येक बार DLG के उपयोग पर हानि अनुमान को अपडेट करना होगा, क्योंकि हर उपयोग के साथ सुरक्षा घटती जाती है।





- DLGs are risk-sharing mechanisms widely used in digital lending and co-lending models, usually capped at 5% of the loan portfolio and often backed by fixed deposits from fintech partners.
- DLG जोखिम-साझाकरण तंत्र हैं, जो डिजिटल लेंडिंग और सह-ऋण मॉडल में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं, आमतौर पर ऋण पोर्टफोलियो के 5% तक सीमित होते हैं और अक्सर फिनटेक भागीदारों की फिक्स्ड डिपॉजिट से समर्थित होते हैं।
- Earlier, in May 2025, RBI had required NBFCs to exclude fintech-provided DLGs from provisioning calculations, leading to higher credit costs and reduced profitability.
- इससे पहले मई 2025 में RBI ने NBFCs को प्रावधान गणना से फिनटेक-प्रदत्त DLG को बाहर रखने का निर्देश दिया था, जिससे क्रेडिट लागत बढ़ी और लाभप्रदता में गिरावट आई थी।



EXAM
Genius





Ques: Why has SEBI constituted a working group recently?

SEBI ने हाल ही में कार्यसमूह क्यों गठित किया है?

- A) To regulate cryptocurrency exchanges / क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंज को विनियमित करने के लिए
- B) To review the framework for ESG Rating Providers / ESG रेटिंग प्रदाताओं के ढांचे की समीक्षा के लिए
- C) To revise mutual fund taxation rules / म्यूचुअल फंड कर नियमों में संशोधन के लिए
- D) To promote IPO listings / IPO लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए
- E) To regulate commodity markets / कमोडिटी बाजार को विनियमित करने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted a dedicated working group to review the regulatory framework for ESG Rating Providers (ERPs).
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने ESG रेटिंग प्रदाताओं (ERPs) के नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेष कार्यसमूह का गठन किया है।
- The move follows feedback from market participants regarding ESG rating practices.
- यह कदम बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के बाद उठाया गया है।
- The panel includes representatives from issuers, investors, domestic & global ERPs, ESG analysts, legal experts, and academia.
- इस पैनल में इश्यूअर्स, निवेशकों, घरेलू व वैश्विक ERPs, ESG विश्लेषकों, कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- The group will review existing regulations, assess global developments, and recommend measures to enhance transparency and reliability in ESG ratings.
- यह कार्यसमूह मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगा, वैश्विक विकास का आकलन करेगा और ESG रेटिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उपाय सुझाएगा।





Ques: Indian Overseas Bank (IOB) expanded its start-up focused banking network by launching exclusive branches in which cities?

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्टार्ट-अप केंद्रित बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किन शहरों में विशेष शाखाएँ शुरू करके किया?

- A) Chennai, Hyderabad, Pune / चेन्नई, हैदराबाद, पुणे
- B) Delhi, Mumbai, Bengaluru / दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु
- C) Kolkata, Ahmedabad, Jaipur / कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर
- D) Kochi, Trivandrum, Coimbatore / कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोयंबटूर
- E) Noida, Gurugram, Faridabad / नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Indian Overseas Bank has expanded its dedicated Start-up Banking Network by launching exclusive start-up focused branches in Delhi, Mumbai, and Bengaluru.
- इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष स्टार्ट-अप केंद्रित शाखाएँ शुरू करके अपने स्टार्ट-अप बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया है।
- This expansion builds on the success of its first start-up focused branch in Chennai, which was launched in June 2024.
- यह विस्तार जून 2024 में चेन्नई में शुरू की गई पहली स्टार्ट-अप शाखा की सफलता पर आधारित है।
- The initiative was announced on the occasion of the 90th Foundation Day of Indian Overseas Bank.
- यह पहल इंडियन ओवरसीज बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित की गई।
- These specialised branches offer a tailored Startup Current Account with benefits such as waiver of Quarterly Average Balance (QAB) for the first 18 months.
- इन विशेष शाखाओं में स्टार्ट-अप के लिए विशेष करंट अकाउंट उपलब्ध है, जिसमें पहले 18 महीनों तक तिमाही औसत शेष राशि (QAB) से छूट दी गई है।
- Additional features include 200 free cheque leaves per month and free NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
- अतिरिक्त सुविधाओं में प्रति माह 200 निःशुल्क चेक पत्ते और निःशुल्क NEFT, RTGS तथा IMPS लेन-देन शामिल हैं।
- The bank also launched 'IOB Gram Sweekar', a rural outreach programme aimed at





Recent News Headlines Related to SEBI

- A SEBI survey revealed that out of 33.72 crore Indian households, only 3.21 crore households (9.5%) invest in securities such as equities, mutual funds, and corporate bonds.
- सेबी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 33.72 करोड़ भारतीय घरों में से केवल 3.21 करोड़ घर (9.5%) ही इक्विटी, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे प्रतिभूति बाज़ार में निवेश करते हैं।
- PhonePe has received approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch its IPO.
- PhonePe को अपना IPO लॉन्च करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की मंजूरी मिली है।
- SEBI proposed allowing Foreign Portfolio Investors (FPIs) to offset their purchase and sale obligations within the same trading day.
- SEBI ने FPIs को एक ही ट्रेडिंग दिन में अपनी खरीद और बिक्री की देनदारियों को समायोजित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया।
- SEBI has proposed a uniform 30-day time lag for sharing and using price data in investor education and awareness programmes.
- सेबी ने निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के उपयोग के लिए 30 दिनों के समान समय अंतराल का प्रस्ताव किया है।
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) mandated that compliance officers of Alternative Investment Fund (AIF) managers must obtain certification from the National Institute of Securities Markets (NISM) by passing the NISM Series-III-C: Securities Intermediaries Compliance (Fund) Certification Examination, effective from January 1, 2027
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) ने अनिवार्य किया है कि वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) प्रबंधकों के अनुपालन अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) से प्रमाणन प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्हें एनआईएसएम सीरीज-III-सी: प्रतिभूति मध्यस्थ अनुपालन (निधि) प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह प्रमाणन 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा।





Ques: What is the key impact of the Reserve Bank of India's (RBI) new lending norms for capital market intermediaries effective from April 1?

1 अप्रैल से प्रभावी RBI के नए ऋण नियमों का पूंजी बाजार मध्यस्थों पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ेगा?

- A) Banks can freely lend for brokers' proprietary trading / बैंक ब्रोकरों के स्वयं के ट्रेडिंग के लिए स्वतंत्र रूप से ऋण दे सकेंगे
- B) Unsecured loans to stock brokers are permitted / स्टॉक ब्रोकरों को बिना गारंटी ऋण देने की अनुमति होगी
- C) All credit to securities firms must be fully collateral-backed / प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया हर ऋण पूरी तरह जमानत-आधारित होगा
- D) Bank guarantees for proprietary trades need no cash collateral / प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए बैंक गारंटी में नकद जमानत की आवश्यकता नहीं होगी
- E) Commodity brokers are exempted from the new norms / कमोडिटी ब्रोकरों को नए नियमों से छूट दी गई है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has tightened lending norms for capital market intermediaries, including stock and commodity brokers involved in proprietary trading.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में लगे स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकरों सहित पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए ऋण नियम सख्त कर दिए हैं।
- Under the new prudential framework, all loans to securities firms must be fully backed by collateral, eliminating unsecured exposure to speculative activities.
- नए सावधानीपूर्ण ढांचे के तहत प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया प्रत्येक ऋण पूरी तरह जमानत से सुरक्षित होना अनिवार्य होगा, जिससे सट्टात्मक गतिविधियों में बिना गारंटी जोखिम समाप्त होगा।
- Banks are prohibited from lending for brokers' own-account (proprietary) trading or for investments made by brokers.
- बैंकों को ब्रोकरों की स्वयं की ट्रेडिंग या उनके निवेश के लिए ऋण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- Bank guarantees issued for proprietary trades must be fully secured, with at least 50% collateral in cash and the remaining portion in cash equivalents or government securities.





Ques: Vast Space signed an order with NASA for its sixth Private Astronaut Mission (PAM) to which destination?

वास्त स्पेस ने नासा के साथ अपना छठा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन (PAM) किस गंतव्य के लिए हस्ताक्षरित किया?

- A) Lunar Gateway / लूनर गेटवे
- B) International Space Station (ISS) / अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)
- C) Tiangong Space Station / तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन
- D) Haven-1 Commercial Station / हेवन-1 वाणिज्यिक स्टेशन
- E) Low Earth Orbit Free Flyer / लो अर्थ ऑर्बिट फ्री फ्लायर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Vast Space signed an order with NASA for its sixth Private Astronaut Mission (PAM) to the International Space Station.
- वास्त स्पेस ने अपने छठे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन (PAM) के लिए नासा के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए समझौता किया।
- The mission is targeted for launch no earlier than Summer 2027 from Florida, USA.
- इस मिशन का प्रक्षेपण ग्रीष्म 2027 से पहले नहीं, फ्लोरिडा (अमेरिका) से प्रस्तावित है।
- This will be Vast's first private astronaut mission in partnership with NASA.
- यह नासा के साथ साझेदारी में वास्त का पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा।
- Astronauts will spend up to 14 days aboard the ISS.
- अंतरिक्ष यात्री ISS पर अधिकतम 14 दिनों तक रहेंगे।
- The mission will use SpaceX's Falcon 9 launch vehicle and Dragon spacecraft for crew transport.
- मिशन में प्रक्षेपण के लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और चालक दल के परिवहन के लिए ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा।
- The final launch date will depend on ISS traffic and operational planning.
- अंतिम प्रक्षेपण तिथि ISS की ट्रैफिक स्थिति और परिचालन योजना पर निर्भर करेगी।
- Vast is also developing Haven-1, planned for launch in 2027, aiming to become the world's first commercial space station.





Ques: The Global Finance & Technology Network (GFTN) was created by which authority?

ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) की स्थापना किस प्राधिकरण द्वारा की गई थी?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Monetary Authority of Singapore / सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण
- C) World Bank / विश्व बैंक
- D) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
- E) International Monetary Fund / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या :

- The Global Finance & Technology Network (GFTN) and the Startup Policy Forum (SPF) announced a strategic collaboration to accelerate fintech and digital innovation.
- GFTN और Startup Policy Forum (SPF) ने फिनटेक और डिजिटल नवाचार को तेज़ करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की।
- The partnership was announced at the Black Swan Summit India 2026 held in Bhubaneswar, Odisha.
- इस साझेदारी की घोषणा भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित Black Swan Summit India 2026 के दौरान की गई।
- GFTN is based in Singapore and was created by the Monetary Authority of Singapore (MAS).
- GFTN सिंगापुर स्थित है और इसकी स्थापना Monetary Authority of Singapore (MAS) द्वारा की गई थी।
- **The collaboration focuses on three goals:**
 - Build Bridges: Create innovation corridors between India and the world.
 - Better Rules: Strengthen dialogue between regulators and tech firms.
 - Go Global: Support Indian startups in expanding internationally.
- इस सहयोग के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
 - ब्रिज बनाना: भारत और विश्व के बीच नवाचार कॉरिडोर बनाना।
 - बेहतर नियम: नियामकों और टेक कंपनियों के बीच संवाद को मजबूत करना।
 - वैश्विक विस्तार: भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में सहायता देना।





- SPF represents over 65 fast-growing Indian startups with a combined valuation of more than USD 100 billion.
- SPF 65 से अधिक तेज़ी से बढ़ते भारतीय स्टार्टअप्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका संयुक्त मूल्यांकन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।



EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to Summits / conference

- The high-level CSR Conclave was organised by the Department of Agriculture & Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
- यह उच्च स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
- PLASTINDIA 2026, one of the world's largest plastics exhibitions, was held at Bharat Mandapam, New Delhi.
- प्लास्टइंडिया 2026, जो विश्व के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदर्शनों में से एक है, का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया।
- The World Audio Visual & Entertainment Summit (WAVES) 2025 was organized to make India a global hub of content creation and promote the "Orange Economy", which integrates content, creativity, and culture into economic growth.
- WAVES 2025 का आयोजन भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने और ऑरेंज इकॉनमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया।
- The Conference of Chief Wildlife Wardens of Tiger Range States and Field Directors of Tiger Reserves was held in Alwar, Rajasthan.
- टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर्स का सम्मेलन राजस्थान के अलवर में आयोजित किया गया।
- The 4th edition of the India–Tanzania Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) meeting was held in Zanzibar.
- भारत-तंज़ानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की चौथी बैठक ज़ांज़ीबार में आयोजित की गई।
- The 14th edition of the World Government Summit 2026 was held in Dubai, UAE.
- वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का 14वां संस्करण दुबई (UAE) में आयोजित किया गया।
- The AI India Impact Summit 2026 has been curated around three core pillars — People, Planet and Progress.
- AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 को पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित किया गया है।





Ques: Google's new undersea cable project will directly connect which two countries?

Google का नया अंडरसी केबल प्रोजेक्ट किन दो देशों को सीधे जोड़ेगा?

- A) India and UK / भारत और यूके
- B) India and Australia / भारत और ऑस्ट्रेलिया
- C) India and United States / भारत और अमेरिका
- D) India and Japan / भारत और जापान
- E) India and Singapore / भारत और सिंगापुर

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Google CEO Sundar Pichai announced an undersea cable project directly linking India and the United States.
- Google के CEO सुंदर पिचाई ने भारत और अमेरिका को सीधे जोड़ने वाले अंडरसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की।
- This will be the second planned subsea cable system directly connecting the two nations.
- यह दोनों देशों को सीधे जोड़ने वाला दूसरा नियोजित अंडरसी केबल सिस्टम होगा।
- The first such initiative was Meta's Project Waterworth.
- इससे पहले ऐसा प्रोजेक्ट Meta का 'Project Waterworth' था।
- Currently, most internet traffic between the two countries passes through relay hubs like Singapore.
- वर्तमान में दोनों देशों के बीच अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक सिंगापुर जैसे रिले प्वाइंट्स के माध्यम से जाता है।
- The new project is expected to improve digital connectivity, data security, and internet speed between India and the U.S.
- यह परियोजना दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और इंटरनेट गति को बेहतर बनाएगी।





Recent News Headlines Related to MoU and agreement:

- Indian Institute of Technology ,Madras Research Park, in partnership with Unicorn India Ventures, launched a 'IITM-Unicorn Frontier Fund I' , a venture capital fund, worth Rs.600 crores to support deeptechology startups in India. It plans to invest in over 25 startups and will allocate about 60% for initial investments and 40% for follow-on funding.
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास रिसर्च पार्क ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के साथ साझेदारी में भारत में डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 600 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड 'आईआईटीएम-यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड I' लॉन्च किया है। यह फंड 25 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश करने की योजना बना रहा है और लगभग 60% प्रारंभिक निवेश और 40% अनुवर्ती फंडिंग के लिए आवंटित करेगा।
- Indian National Science Academy and National Institute of Science Communication and Policy Research signed a Memorandum of Understanding (MoU) to promote collaborative activities in science communication and evidence-based science policy research.
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने विज्ञान संचार और साक्ष्य-आधारित विज्ञान नीति अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए।
- India and France amended the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) to boost bilateral trade and investments.
- भारत और फ्रांस ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए DTAA में संशोधन किया।
- Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) and Hindustan Shipyard Limited (HSL) signed a Memorandum of Understanding (MoU) in Kolkata to form a strategic consortium for executing a large-scale national shipbuilding programme.
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने कोलकाता में एक बड़े पैमाने के राष्ट्रीय जहाज निर्माण कार्यक्रम को लागू करने के लिए रणनीतिक कंसोर्टियम बनाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- Airports Authority of India (AAI) has signed an MoU with Bharat Taxi to improve last-mile connectivity at select airports.
- एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने चुनिंदा हवाई अड्डों पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत टैक्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।





Ques: Which ministry is organising the National Conference on Safety of Women at Workplace (SHe-Box) on 14 February 2026 at Vigyan Bhawan, New Delhi?

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (SHe-Box) पर 14 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है?

- A) Ministry of Labour and Employment / श्रम और रोजगार मंत्रालय
- B) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- C) Ministry of Women and Child Development / महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- D) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- E) Ministry of Education / शिक्षा मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Conference on Safety of Women at Workplace (SHe-Box) is being organised by the Ministry of Women and Child Development on 14 February 2026 at Vigyan Bhawan.
- कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (SHe-Box) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 14 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- The objective of the conference is to reaffirm the Government's commitment to ensuring safe, dignified and harassment-free workplaces for women.
- इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना है।
- It also aims to strengthen the implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
- यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने पर भी केंद्रित है।
- The SHe-Box (Sexual Harassment electronic Box) portal was launched by MWCD on 29 August 2024.
- SHe-Box (सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) पोर्टल को 29 अगस्त 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- The portal is a secure, user-friendly and multilingual digital platform that enables





online complaint filing and ensures automatic forwarding of complaints to the Internal Committee (IC) or Local Committee (LC).

- यह पोर्टल एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल और बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उन्हें आंतरिक समिति (IC) या स्थानीय समिति (LC) तक स्वतः भेजने की सुविधा देता है।
- It provides real-time complaint tracking along with strict confidentiality safeguards for complainants.
- यह शिकायतों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग और शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।



EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to Schemes

- The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, launched the 'Sthree Suraksha Scheme'.
- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 'स्त्री सुरक्षा योजना' की शुरुआत की।
- The Delhi Lakhpati Bitiya Yojana has replaced the Delhi Ladli Scheme (2008) and supports girls from birth to graduation.
- दिल्ली लखपति बिटिया योजना ने 2008 की दिल्ली लाडली योजना की जगह ली है और जन्म से स्नातक तक बालिकाओं को सहायता देती है।
- The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) approved the construction of over 3.53 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0).
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी।
- The Ministry of Parliamentary Affairs unveiled the upgraded National Youth Parliament Scheme (NYPS 2.0) web portal to significantly expand the reach and inclusivity of the Youth Parliament Programme across India.
- संसदीय कार्य मंत्रालय ने यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम की पहुँच और समावेशन बढ़ाने के लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम (NYPS 2.0) का उन्नत वेब पोर्टल लॉन्च किया।
- Mukhyamantri Gramotthan Yojana (MGY) was launched by Bhupendra Patel, the Chief Minister of Gujarat.
- मुख्यमंत्री ग्रामोन्नयन योजना (MGY) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू की गई।
- The Cashless Treatment for Road Accident Victims Scheme, 2025 has been notified under Section 162 of the Motor Vehicles Act, 1988.
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- The Mukhya Mantrir Eti Koli Duti Paat Scheme was launched by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma.
- मुख्यमंत्री एति कोली दूटी पाट योजना असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा शुरू की गई।





Ques: The AI models 'Vikram' launched by Sarvam AI are primarily designed for what feature?

Sarvam AI द्वारा लॉन्च 'विक्रम' एआई मॉडल मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए डिजाइन किए गए हैं?

- A) Only English text processing / केवल अंग्रेजी टेक्स्ट प्रोसेसिंग
- B) Voice-command usage and support for 22 Indian languages / वॉइस कमांड आधारित उपयोग और 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन
- C) Military surveillance applications / सैन्य निगरानी उपयोग
- D) Cryptocurrency trading / क्रिप्टोकॉरेन्सी ट्रेडिंग
- E) Space research simulations / अंतरिक्ष अनुसंधान सिमुलेशन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Sarvam AI unveiled two AI language models named 'Vikram' at an AI Summit in New Delhi.
- Sarvam AI ने नई दिल्ली में आयोजित AI समिट में 'विक्रम' नामक दो एआई भाषा मॉडल लॉन्च किए।
- The models are specifically designed to function through voice commands.
- ये मॉडल विशेष रूप से वॉइस कमांड के माध्यम से कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- They support and are accessible in 22 Indian languages, strengthening multilingual AI capability.
- ये 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे बहुभाषी एआई क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- The initiative aims to significantly improve AI performance in Indian languages, marking a milestone in India's AI ecosystem.
- यह पहल भारतीय भाषाओं में एआई प्रदर्शन सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





Ques: The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved India's first underwater road-rail tunnel beneath which river?

कैबिनेट समिति on Economic Affairs (CCEA) ने भारत की पहली अंडरवॉटर रोड-रेल सुरंग किस नदी के नीचे स्वीकृत की है?

- A) Ganga / गंगा
- B) Yamuna / यमुना
- C) Brahmaputra / ब्रह्मपुत्र
- D) Godavari / गोदावरी
- E) Narmada / नर्मदा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the construction of India's first underwater twin-tube road-cum-rail tunnel beneath the Brahmaputra River in Assam.
- कैबिनेट समिति on Economic Affairs (CCEA) ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब रोड-कम-रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है।
- The total length of the project is 33.7 km, which includes a 15.79 km long underwater twin-tube tunnel.
- इस परियोजना की कुल लंबाई 33.7 किमी है, जिसमें 15.79 किमी लंबी अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है।
- The project will be developed under the Engineering, Procurement and Construction (EPC) mode at an estimated cost of ₹18,662 crore.
- यह परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के तहत लगभग ₹18,662 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी।
- The tunnel will improve connectivity between Gohpur (NH-15) and Numaligarh (NH-715).
- यह सुरंग गोहपुर (NH-15) और नुमालीगढ़ (NH-715) के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी।
- The distance between the two points will reduce from about 240 km to just 34 km, while travel time will drop from nearly 6 hours to around 20 minutes.
- इससे दूरी लगभग 240 किमी से घटकर 34 किमी रह जाएगी और यात्रा समय लगभग 6 घंटे से घटकर 20





मिनट हो जाएगा।

- Additionally, the Cabinet approved three multitracking railway projects: Kasara–Manmad, Delhi–Ambala, and Ballari–Hosapete third and fourth lines across multiple states.
- इसके अलावा, कैबिनेट ने कासारा–मनमाड, दिल्ली–अंबाला और बल्लारी–होसपेटे रेलखंडों पर तीसरी और चौथी लाइन के मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है।



EXAM
Genius





Ques: The Chief Minister Skill Development Scheme approved by the Delhi Government is aimed at supporting artisans engaged in which sectors?

दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किन क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों को समर्थन देने के लिए है?

- A) IT and Software Services / आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएँ
- B) Automobile and Engineering Industries / ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग
- C) Khadi, Handloom and Cottage Industries / खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योग
- D) Construction and Real Estate / निर्माण और रियल एस्टेट
- E) Tourism and Hospitality / पर्यटन और आतिथ्य

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Delhi Government has approved the Chief Minister Skill Development Scheme to support artisans engaged in khadi, handloom and cottage industries.
- दिल्ली सरकार ने खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योगों से जुड़े कारीगरों के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है।
- The initiative was announced by Chief Minister Rekha Gupta, who highlighted that artisans are custodians of Delhi's cultural heritage and should be connected to modern markets.
- इस पहल की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की, जिन्होंने कहा कि कारीगर दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं और उन्हें आधुनिक बाजारों से जोड़ना आवश्यक है।
- The scheme aims to provide structured skill training to artisans.
- इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को संरचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- It also focuses on enabling digital access and marketing support.
- योजना डिजिटल पहुंच और विपणन सहायता उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित है।
- Financial assistance will be offered to improve income levels and livelihood opportunities.
- आय और आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।





Ques: What is the purpose of NHAI's bee corridor initiative?

NHAI के बी कॉरिडोर पहल का उद्देश्य क्या है?

- A) To increase highway toll revenue / राजमार्ग टोल राजस्व बढ़ाना
- B) To reduce ecological stress and promote biodiversity / पारिस्थितिक दबाव कम करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना
- C) To build expressways in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे बनाना
- D) To promote electric vehicles / इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना
- E) To develop industrial zones / औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- National Highways Authority of India (NHAI) will develop bee corridors along national highways.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बी कॉरिडोर विकसित करेगा।
- The initiative aims to reduce ecological stress, improve pollination, and promote biodiversity conservation.
- इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिक दबाव को कम करना, परागण को बढ़ावा देना और जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- At least three bee corridors are expected to be developed in the next financial year starting April 1.
- 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन बी कॉरिडोर विकसित किए जाने की संभावना है।
- The announcement was made by the Ministry of Road Transport and Highways.
- इसकी घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई।





Ques: Which two Central Public Sector Enterprises (CPSEs) signed an MoU to collaborate on thermal captive power and renewable energy projects?

थर्मल कैप्टिव पावर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग के लिए किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) National Aluminium Company Limited (NALCO) and Coal India Limited / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और कोल इंडिया लिमिटेड
- B) National Aluminium Company Limited (NALCO) and NLC India Limited / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड
- C) Hindustan Copper Limited and NLC India Limited / हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड
- D) Steel Authority of India Limited (SAIL) and NTPC / स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और एनटीपीसी
- E) National Aluminium Company Limited (NALCO) and NTPC / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और एनटीपीसी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- National Aluminium Company Limited (NALCO), a Navratna Central Public Sector Enterprise, signed an MoU with NLC India Limited (NLCIL).
- नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The MoU aims to strengthen collaboration on a 1080-MW Thermal Captive Power Project and renewable energy development.
- इस समझौते का उद्देश्य 1080 मेगावाट की थर्मल कैप्टिव पावर परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग को मजबूत करना है।
- NALCO is a Navratna CPSE under the Ministry of Mines and is a major player in bauxite, alumina, aluminium, and power generation.
- NALCO खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न CPSE है और बॉक्साइट, एल्यूमिना, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- NLC India Limited is a CPSE under the Ministry of Coal, engaged in lignite mining, thermal power generation, and renewable energy projects.





Ques: Why was Galgotias University removed from the India AI Impact Summit 2026?

गलगोटियास यूनिवर्सिटी को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से क्यों हटाया गया?

- A) Technical malfunction at the stall / स्टॉल पर तकनीकी खराबी
- B) Security violation / सुरक्षा उल्लंघन
- C) Presenting a Chinese-made robot as its own in-house innovation / चीनी निर्मित रोबोट को अपनी इन-हाउस नवाचार के रूप में प्रस्तुत करना
- D) Non-payment of participation fees / भागीदारी शुल्क का भुगतान न करना
- E) Political protest at the venue / स्थल पर राजनीतिक विरोध

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Galgotias University was asked to vacate its stall at the India AI Impact Summit 2026 on February 18, 2026.
- गलगोटियास यूनिवर्सिटी को 18 फरवरी 2026 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया।
- The action followed allegations that the university showcased the Chinese-manufactured robotic dog Unitree Go2 as its own in-house innovation under the name "Orion."
- यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि विश्वविद्यालय ने चीनी निर्मित रोबोटिक डॉग Unitree Go2 को "Orion" नाम से अपनी स्वयं की विकसित तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया।
- The controversy led to claims of misrepresentation, after which the university issued a clarification and apology stating there was no institutional intent to mislead.
- इस विवाद के बाद गलत प्रस्तुतीकरण के आरोप लगे और विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण व माफी जारी करते हुए कहा कि गलत जानकारी देने का कोई संस्थागत इरादा नहीं था।





Ques: The Shahpurkandi Dam is built on which river?

शाहपुरकंडी बांध किस नदी पर बनाया गया है?

- A) Chenab / चिनाब
- B) Ravi / रावी
- C) Jhelum / झेलम
- D) Beas / ब्यास
- E) Sutlej / सतलुज

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- The Shahpurkandi Dam has been constructed on the Ravi River.
- शाहपुरकंडी बांध रावी नदी पर बनाया गया है।
- After its completion, additional water that earlier flowed into Pakistan will now be diverted for irrigation use in India.
- इसके पूरा होने के बाद, जो अतिरिक्त पानी पहले पाकिस्तान चला जाता था, अब उसे भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा।
- The dam is located on the Punjab–Jammu border and is expected to become operational soon.
- यह बांध पंजाब–जम्मू सीमा पर स्थित है और जल्द ही चालू होने की संभावना है।
- The project will significantly boost irrigation in Jammu and Kashmir (especially the Kathua region) and Punjab.
- यह परियोजना जम्मू-कश्मीर (विशेषकर कठुआ क्षेत्र) और पंजाब में सिंचाई को बढ़ावा देगी।
- Work on such projects has accelerated following developments related to the Indus Waters Treaty.
- इस प्रकार की परियोजनाओं पर कार्य सिंधु जल संधि से संबंधित घटनाओं के बाद तेज हुआ है





Ques: The Centre for Development of Telematics (C-DOT) signed a landmark MoU with which institution to promote telecom innovation and cybersecurity research?

दूरसंचार विकास केंद्र (C-DOT) ने दूरसंचार नवाचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Indian Institute of Technology Delhi / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
- B) Rashtriya Raksha University / राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
- C) National Defence College / राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
- D) Indian Institute of Science / भारतीय विज्ञान संस्थान
- E) National Institute of Electronics & IT / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Centre for Development of Telematics (C-DOT), under the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications, signed a landmark MoU with Rashtriya Raksha University (RRU).
- दूरसंचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत C-DOT ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के साथ एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The collaboration focuses on promoting telecom innovation and advanced cybersecurity research.
- यह सहयोग दूरसंचार नवाचार और उन्नत साइबर सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- A key initiative under the MoU is the establishment of an Innovation-cum-Experience Centre at RRU.
- MoU के तहत RRU में एक इनोवेशन-कम-एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- The centre will deploy TRINETRA, a unified AI-powered cyber security solution developed indigenously by C-DOT.
- इस केंद्र में C-DOT द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित TRINETRA नामक एकीकृत AI-संचालित साइबर सुरक्षा समाधान तैनात किया जाएगा।
- Rashtriya Raksha University is an Institution of National Importance under the Ministry of Home Affairs, focusing on internal security, cyber defence, national security studies, and technology-driven security solutions.





Ques: What was the theme of the 18th Foundation Day of the National Statistical Systems Training Academy (NSSTA)?

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA) के 18वें स्थापना दिवस का विषय क्या था?

- A) Strengthening Digital Governance for India / भारत के लिए डिजिटल शासन को सशक्त बनाना
- B) Reimagining Capacity Building for Official Statistics to achieve Vision of Viksit Bharat@2047 / विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना
- C) Data-Driven Growth for Atmanirbhar Bharat / आत्मनिर्भर भारत के लिए डेटा-आधारित विकास
- D) Modernising Statistical Systems for Global Competitiveness / वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सांख्यिकी प्रणालियों का आधुनिकीकरण
- E) Inclusive Development through Evidence-Based Policy / साक्ष्य-आधारित नीति के माध्यम से समावेशी विकास

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The National Statistical Systems Training Academy (NSSTA), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation, celebrated its 18th Foundation Day.
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA) ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया।
- The theme of the Foundation Day was “Reimagining Capacity Building for Official Statistics to achieve Vision of Viksit Bharat@2047.”
- स्थापना दिवस का विषय था “विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना।”
- NSSTA was established to strengthen India’s National Statistical System (NSS) by enhancing skills and capacities in official statistics.
- NSSTA की स्थापना भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (NSS) को सुदृढ़ करने हेतु आधिकारिक सांख्यिकी में कौशल और क्षमता विकास के लिए की गई थी।





Ques: Why did the Government of India lift the wheat export ban after four years?

भारत सरकार ने चार वर्षों बाद गेहूं निर्यात प्रतिबंध क्यों हटाया?

- A) To control domestic inflation only / केवल घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
- B) Due to surplus production and to ensure remunerative prices for farmers / अधिशेष उत्पादन और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए
- C) To meet WTO obligations / डब्ल्यूटीओ दायित्वों को पूरा करने के लिए
- D) Due to decline in wheat acreage / गेहूं के रकबे में गिरावट के कारण
- E) To reduce buffer stock costs / बफर स्टॉक लागत कम करने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India lifted the wheat export ban after four years due to comfortable domestic availability and to ensure remunerative prices for farmers.
- भारत सरकार ने घरेलू उपलब्धता संतोषजनक होने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार वर्षों बाद गेहूं निर्यात प्रतिबंध हटाया।
- Wheat is a Rabi crop grown mainly in tropical, sub-tropical and temperate regions.
- गेहूं एक रबी फसल है, जिसे उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- It requires cool and moist weather during the vegetative growth period, followed by dry and warm weather for grain maturity and ripening.
- इसके लिए वृद्धि अवधि में ठंडा और नम मौसम तथा दाने के पकने के लिए शुष्क और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।
- The optimum temperature for wheat cultivation is 20–25°C with ideal rainfall of 50–75 cm.
- गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 20–25 डिग्री सेल्सियस और उपयुक्त वर्षा 50–75 सेमी होती है।
- India is the world's second-largest producer of wheat, contributing around 14% of global output, and has the largest area under wheat cultivation.
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 14% योगदान देता है और इसके पास गेहूं का सबसे बड़ा रकबा है।
- The top wheat-producing states in India are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Punjab.





Ques: When is GalaxEye's 'Mission Drishti' scheduled to be launched?

GalaxEye का 'Mission Drishti' कब लॉन्च किया जाएगा?

- A) 2024
- B) 2025
- C) 2026
- D) 2027
- E) 2028

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- GalaxEye has announced that its upcoming satellite mission 'Mission Drishti' is scheduled for launch in 2026.
- GalaxEye ने घोषणा की है कि उसका सैटेलाइट मिशन 'Mission Drishti' वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा।
- The satellite will integrate Nvidia's Jetson Orin GPU architecture to enable advanced AI processing directly in orbit.
- इस सैटेलाइट में Nvidia का Jetson Orin GPU आर्किटेक्चर शामिल होगा, जिससे कक्षा में ही उन्नत AI प्रोसेसिंग संभव होगी।
- It aims to enhance real-time processing and delivery of Earth observation data and will feature GalaxEye's SyncFused OptoSAR architecture.
- इसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन डेटा की रियल-टाइम प्रोसेसिंग और विश्लेषण को बेहतर बनाना है, साथ ही इसमें SyncFused OptoSAR आर्किटेक्चर शामिल होगा।
- The announcement was made at the IndiaAI Impact Summit 2026 in New Delhi.
- इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित IndiaAI Impact Summit 2026 में की गई।





Ques: Which of the following are the Umbrella Missions of the Ministry of Women & Child Development (MWCD)?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की अम्ब्रेला मिशनों निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?

- A) Mission Saksham Anganwadi & Poshan 2.0, Mission Shakti, Mission Vatsalya / मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य
- B) Mission Poshan Abhiyaan, Mission Swachh Bharat, Mission Vatsalya / मिशन पोषण अभियान, मिशन स्वच्छ भारत, मिशन वात्सल्य
- C) Mission Shakti, Mission Jal Jeevan, Mission Poshan 2.0 / मिशन शक्ति, मिशन जल जीवन, मिशन पोषण 2.0
- D) Mission Saksham Anganwadi, Mission Ayushman Bharat, Mission Vatsalya / मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन आयुष्मान भारत, मिशन वात्सल्य
- E) Mission Poshan Abhiyaan, Mission Beti Bachao Beti Padhao, Mission Vatsalya / मिशन पोषण अभियान, मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन वात्सल्य

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Women & Child Development (MWCD) implements three Umbrella Missions to streamline and strengthen women- and child-centric schemes.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं को सुदृढ़ करने हेतु तीन अम्ब्रेला मिशनों का क्रियान्वयन करता है।

1. Mission Saksham Anganwadi & Poshan 2.0

(Also known as Mission Poshan 2.0)

- Objective: Improve nutrition and health indicators of women, children, and adolescent girls.
- उद्देश्य: महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार।
- Key Components (Reorganisation of):
 - Anganwadi Services
 - POSHAN Abhiyaan
 - Scheme for Adolescent Girls





2. Mission Shakti

- Objective: Ensure safety, security, and empowerment of women.
- उद्देश्य: महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
- It has two verticals:

A. Sambal (Safety & Protection)

- One Stop Centres (OSC)
- Women Helpline (181)
- Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
- Nari Adalat

B. Samarthya (Empowerment)

- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)
- Shakti Sadan
- Sakhi Niwas
- National Hub for Empowerment of Women (NHEW)
- Palna (Crèche Facility)

3. Mission Vatsalya

- Focus: Protection, care, and welfare of children in difficult circumstances.
- फोकस: कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण।
- Includes:
 - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
- Objectives:
 - Support children in difficult circumstances
 - Provide holistic development
 - Encourage innovation
 - Ensure convergence across departments

Evaluation & Monitoring

- A third-party evaluation of these missions (FY 2019–2024) was conducted by NITI Aayog.
- The study found the schemes to be relevant, impactful, and well-aligned with national development goals.





Ques: Which event will be hosted by the Indian Army as the first-ever international military adventure competition in February 2026?

फरवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा पहली बार आयोजित किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक प्रतियोगिता कार्यक्रम कौन-सा है?

- A) International Mountain Warfare Cup / अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय युद्ध कप
- B) International Military Adventure Challenge Cup (IMACC) / अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप
- C) Global Armed Forces Endurance Meet / वैश्विक सशस्त्र बल सहनशक्ति प्रतियोगिता
- D) Himalayan Joint Military Games / हिमालय संयुक्त सैन्य खेल
- E) International Defence Sports Championship / अंतरराष्ट्रीय रक्षा खेल चैम्पियनशिप

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Indian Army will host the first-ever International Military Adventure Challenge Cup (IMACC) 2026 from 18–23 February 2026.
- भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी 2026 तक पहली बार अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप (IMACC) 2026 की मेजबानी करेगी।
- The event will be held in the foothills of the Eastern Himalayas.
- यह आयोजन पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित किया जाएगा।
- The objective of IMACC is to enhance military cooperation, build camaraderie, and test soldiers' endurance in challenging mountainous terrain.
- IMACC का उद्देश्य सैन्य सहयोग बढ़ाना, आपसी सौहार्द विकसित करना और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में सैनिकों की सहनशक्ति का परीक्षण करना है।
- Military teams from seven friendly foreign nations will participate: Bhutan, Brazil, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Sri Lanka, and Saudi Arabia.
- सात मित्र देशों की सैन्य टीमों में भाग लेंगी: भूटान, ब्राज़ील, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब।
- Indian participants will include the Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard, and Indo-Tibetan Border Police (ITBP).
- भारतीय प्रतिभागियों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) शामिल होंगे।





Ques: How much Special Economic Package did India announce during the visit of Seychelles President Dr. Patrick Herminie?

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा के दौरान भारत ने कितने मूल्य का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया?

- A) USD 100 million
- B) USD 150 million
- C) USD 175 million
- D) USD 200 million
- E) USD 250 million

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Patrick Herminie, President of Seychelles, visited India on his first official visit since assuming office in 2025. The visit coincided with the 50th anniversary of India–Seychelles diplomatic relations (1976–2026).
- सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा की। यह यात्रा भारत–सेशेल्स कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ (1976–2026) के अवसर पर हुई।
- India announced a USD 175 million Special Economic Package, including:
 - USD 125 million Line of Credit (low-interest loan)
 - USD 50 million Grant Assistance (free aid)
- भारत ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया, जिसमें:
 - 125 मिलियन डॉलर की रियायती ऋण सहायता
 - 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है।
- Key assistance included 10 ambulances, 1,000 metric tonnes of grains & lentils, refit of petrol ship Zoraster, 10 utility vehicles, and 5 Laser Radial boats.
- प्रमुख सहायता में 10 एंबुलेंस, 1,000 मीट्रिक टन अनाज व दालें, पेट्रोल पोत Zoraster का निःशुल्क पुनर्निर्माण, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 लेजर रेडियल नौकाएं शामिल हैं।
- Both nations adopted the India–Seychelles Joint Vision for Sustainability, Economic Growth and Security through Enhanced Linkages (SESEL Vision) to deepen cooperation in health, digital infrastructure, maritime security, environment, and





culture.

- दोनों देशों ने स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु SESEL संयुक्त विजन को अपनाया।
- Seychelles also expressed support for India's MAHASAGAR (Maritime Heads for Active Security and Growth for All in the Region) initiative.
- सेशेल्स ने भारत की MAHASAGAR समुद्री पहल का समर्थन भी व्यक्त किया।



EXAM
Genius

